भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-375

उत्तर देने की तारीख-03/12/2025

छात्रों के बीच डिजिटल पहुँच और अधिगम अंतराल

375 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी स्कूलों में ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिनकी वर्तमान में डिजिटल उपकरणों या इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच नहीं है, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) डिजिटल और मिश्रित अधिगम प्लेटफार्मों को अपनाने के बाद नामांकन और उपस्थिति के संबंध में क्या रुझान दर्ज किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईसीटी और स्मार्ट कक्षा अवसंरचना के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(घ) डिजिटल अधिगम अंतराल, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित छात्रों के बीच, को कम करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की डिजिटल पहल विशेष रूप से "आईसीटी और स्मार्ट क्लासरूम घटक" छात्रों को बुनियादी ढांचा प्रदान करती है और कक्षाओं को तकनीक-संचालित कक्षा में बदल देती है। संसाधनों की विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठाकर, मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरैक्टिव गतिविधियों का उपयोग करके छात्रों की व्यस्तता बढ़ाई जाती है। यह छात्रों के लिए गहरी समझ, सहयोग और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है, जिससे उनके समग्र शैक्षिक अनुभव को समृद्ध किया जा सकता है।

समग्र शिक्षा के आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम घटक के तहत, स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान निम्नलिखित दो विकल्पों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है:

विकल्प I: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे अपनी जरूरत और आवश्यकता के अनुसार या तो आईसीटी या स्मार्ट क्लासरूम का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में, एक अतिरिक्त आईसीटी प्रयोगशाला पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण शिक्षण उपकरण और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और संसाधन सहायता जैसे हार्डवेयर की खरीद करने की छूट है। इसमें स्वीकृत स्कूलों की संख्या के लिए आनुपातिक आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लिए समर्थन शामिल होगा।

विकल्प II: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले से ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट क्लासरूम/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 1,77,088 आईसीटी प्रयोगशालाएं और 1,76,728 स्मार्ट क्लासरूम संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें वर्ष 2024-25 में सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को संतृप्त करने के लिए संस्वीकृत 3,564 आईसीटी प्रयोगशालाएं और 3,655 स्मार्ट क्लासरूम शामिल हैं। इसमें 20,553 आईसीटी लैब और 29,910 स्मार्ट क्लासरूम भी शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2025-26 में सभी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को कार्यात्मक आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम से परिपूर्ण करने के लिए अनुमोदन दिया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए एकीकृत जिला सूचना (यूडाइज+) प्रणाली विकसित की है। वर्ष 2022-23 से, यूडाइज+ व्यक्तिगत छात्रवार डेटा कैप्चर करता है और छात्रों की रजिस्ट्री बनाता है।

यूडाइज + 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, आईसीटी/कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम (ग्रेड VI और उससे ऊपर के स्कूल) और इंटरनेट कनेक्शन वाले सरकारी स्कूलों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

यूडाइज+ के अनुसार, स्कूल शिक्षा के सभी चरणों में ड्रॉपआउट दर में निम्नानुसार कमी दर्ज की गई है

ड्रॉपआउट दर		
स्तर	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
प्रारंभिक	3.7	2.3
मध्य	5.2	3.5
माध्यमिक	10.9	8.2

दिनांक 17 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तत्वावधान में देश भर में शिक्षा के लिए मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की

प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। पीएम ई-विद्या में भारत सरकार में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों (एबी)/अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि वे ग्रेड 1 से 12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा) सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जेटिक पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का 'एक राष्ट्र, एक डिजिटल' मंच है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त भारत संस्थानों ने बहुभाषावाद को सक्षम करने वाली मातृभाषा स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.7 लाख रुपये से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है। छात्रों के पास दीक्षा पर 450 से अधिक वर्चुअल लैब और 100 वर्चुअल स्किल लैब (हिंदी और अंग्रेजी में 50-50) तक पहुंच है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बजट 2025 में बीएसएनएल द्वारा चरणबद्ध तरीके से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान की घोषणा की है।

समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लासरूम के लिए वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

(रूपये लाख में)

वित्त वर्ष	आईसीटी प्रयोगशाला		स्मार्ट क्लासरूम	
	आवंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां	आवंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां
2022-23	41,824.0	71,209.7*	73,823.20	66,276.64
2023-24	55,904.4	78,672.6*	53,729.70	36,947.14
2024-25	54,371.6	11,850.3	59,518.80	11,525.20

* व्यय में पिछले वर्ष के अनुमोदन का स्पिलओवर शामिल है।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी द्वारा "छात्रों के बीच डिजिटल पहुँच और अधिगम अंतराल" के संबंध में दिनांक 03.12.2025 को पूछे गए राज्य सभा आतारांकित प्रश्न संख्या 375 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आईसीटी/कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम (ग्रेड VI और उससे ऊपर के स्कूल) और इंटरनेट कनेक्शन वाले सरकारी स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**आईसीटी/कंप्यूटर लैब**	**स्मार्ट क्लासरूम**	**इंटरनेट**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	148	135	148
आंध्र प्रदेश	3208	8263	10583
अरुणाचल प्रदेश	305	526	436
असम	6552	8457	10894
बिहार	7240	9360	32923
चंडीगढ़	115	114	115
छत्तीसगढ़	2658	6257	11852
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	200	202	210
दिल्ली	1092	920	1157
गोवा	108	81	130
गुजरात	15743	19480	21759
हरियाणा	3585	4247	4683
हिमाचल प्रदेश	2705	2800	3663
जम्मू और कश्मीर	2851	2646	4329
झारखंड	4379	4643	8686
कर्नाटक	6509	9459	11631
केरल	2001	1990	2250
लद्दाख	177	289	248
लक्षद्वीप	20	17	21
मध्य प्रदेश	3914	10345	12933
महाराष्ट्र	5903	18690	14433
मणिपुर	567	419	385

मेघालय	307	112	769
मिजोरम	371	287	904
नागालैंड	255	647	489
ओडिशा	7625	12537	18654
पुडुचेरी	184	170	186
पंजाब	6352	6190	6353
राजस्थान	13956	15271	27601
सिक्किम	327	361	237
तमिलनाडु	12908	6763	12678
तेलंगाना	5061	6996	6405
त्रिपुरा	1061	978	1193
उत्तर प्रदेश	3935	18325	18487
उत्तराखंड	1582	2448	3260
पश्चिम बंगाल	9430	2869	9727
भारत	133334	183294	260412

स्त्रोत: यूडाइज+ 2024-25